

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 795

(03 दिसम्बर, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के अन्तगत काय सारणी म संशोधन

795. श्री सी.एन. जयदेवन:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री पी. नागराजन:

श्री दुष्यंत चौटाला:

श्री टी.जी. वकटेश बाबू:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्रीमती कोथापल्लौ गीता:

श्री नन्दो एल्लैया:

श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तगत विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए क्षेत्रों म मजदूरों काय सूची म संशोधन करने तथा श्रम दिवसों को संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मनरेगा योजना के अंतगत नए काय शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसको स्थिति क्या है; और

(घ) मनरेगा योजना म परिवर्तन के मामले म सरकार द्वारा क्या वित्तीय जटिलताओं का सामना किया जा सकता है और मनरेगा योजना के अन्तगत विशेषकर महिलाओं पर जोर देते हुए लाभार्थियों पर ग्रामीण रोजगार और गरीबी पर इसके क्या प्रभाव पड़गे?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री

(श्री सुदशन भगत)

(क) और (ख): सरकार ने देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित अथवा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) म प्रति परिवार 100 दिन के अलावा अकुशल मजदूरों काय के अतिरिक्त 50 दिन के लिए जरूरी प्रावधान किया है।

(ग) और (घ): राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त सुझावों और फांडबैंक के आधार पर नए कार्यों और दिशा-निर्देशों सहित अनुसूची म समय-समय पर बदलाव और संशोधन किए जाते ह।
